(ख) महाराष्ट्र सरकार ने ऐसे कितने प्रस्ताव भेजे हैं तथा इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी;

(ग) क्या सरकार सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत चीनी मिलें स्थापित करने हेतु ऋण देती है;

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या सावधिक ऋण देने वाली संस्थाएं भी इस संबंध में चीनी मिलों की सहायता करेंगी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 31-1-1994 तक सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना के के लिए विचारार्थ लंबित आवेदनों की राज्य-वार संख्या निम्नानुसार है :—

1. महाराष्ट्र	231
2. बिहार	2
3. कर्नाटक	8
4. उत्तर प्रदेश	1
कुल :	242

(ख) 31-1-1994 तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से 231 आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से 225 आवेदनों की जांच समिति द्वारा जांच कर ली गई है । जांच के बाद खाद्य मंत्रालय की सिफारिशें लाइसेंस समिति द्वारा विचार के लिए उद्योग मंत्रालय को भेज दी गई हैं जिसके बाद उस मंत्रालय द्वारा आशय-पत्र जारी किए जाएंगें । शेष 6 आवेदनों पर कारवाई की जा रही है ।

(ग) और (घ) सरकार सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलें लगाने के लिए कोई ऋण उपलब्ध नहीं कराती है । तथापि, ऐसे ऋण वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपक्रमों को सीधे उपलब्ध कराए जाते हैं ।

(ङ) वित्तीय संस्थाओं ने सूचित किया है सहकारी क्षेत्र में चीनी इकाइयों के अवधि ऋणों के आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा जब संबंधित राज्य सरकारें वर्तमान सहकारी चीनी तथा वस्त्र इकाइयों द्वारा ऋणों की वापसी में की गई चूक, जिनके ऋणों की राज्य सरकारों द्वारा गारंटी दी गई थी, को क्लीयर कर दें ।

Increase in Prices of Foodgrains

1608. SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN : Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether the prices of food grains hiked in the wake of Budget would be reconsidered and brought to normal;

(b) what steps the Minister is contemplating to bring down this spiralling foodgrains prices;

(c) what is the reason for this price hike of food grains;

(d) whether the Minister is aware of the election promises that prices will be rolled down to that of 1987; and

(e) if so, what stringent measures the food Minister intends to take to reduce the hike prices of food grains ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) to (c) To partially absorb the increase in the procurement prices of wheat and paddy paid to farmers during 1993-94 and consequential increase in their procurement cost, the Central Issue Prices (ex-FCI godown) of wheat and rice issued to the States/Union Territories by Food Corporation of India from the central pool for the public distribution

system (PDS) have been increased with effect from 1-2-1994 as under :

(Rs. per quintal)

Commodity	Central Issue Price (ex-FCI godown)		Increase per quintal
	Prior to 1-2-1994	from 1-2-1994	
Wheat	330.00	402.00	72.00
Rice : Common	437.00	537.00	100.00
Fine	487.00	617.00	120.00
Superfine	518.00	648.00	130.00

(d) and (e) Central Government bears the burden of a huge amount of food subsidy for making available foodgrains under PDS and other welfare schemes, viz. RPDS/ ITDP etc.

In order to keep the open market prices of wheat and rice at reasonable level, the Food Corporation of India have undertaken open sale of wheat and rice from the Central Pool. This has had a sobering effect on the open market prices of these commodities.

Amendment of Warehouse Corporation Act

1609. SHRI SOM PAL : Will the Minister of FOOD be pleased to refer to Unstarred Question 3332 given in the Rajya Sabha on 24th December, 1993 and state :

(a) what are the major considerations for amending the Warehouse Corporation Act, 1962 and what are the salient features of the proposed Bill, and

(b) when the new bill is likely to be introduced ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI) : (a) One of the objectives behind the proposed amendments to the Warehousing Corporations Act is to facilitate the re-organisation of the Board of Directors of the Central Warehousing Corporation with a view, inter-alia, to provide greater representation to professional bodies and other interested sections like farmers etc. Another amendment will facilitate the setting up of warehouses abroad by the Central Warehousing Corporation, to help in our exports. Certain other amendments are also proposed which would facilitate the smooth functioning of the Central Warehousing Corporation and of the State Warehousing Corporations.

(b) The proposed amendments will be effected after necessary administrative formalities for amending the said Act have been completed.

भारतीय खाद्य निगम में अस्थायी श्रमिकों को नियमित किया जाना

1610. **श्री मूल चन्द सीणा** : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और अन्य स्थानों पर तैनात अस्थायी श्रमिकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन श्रमिकों को नियमित करने की नीति/मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में कितने श्रमिकों को नियमित करने की बजाय सेवा से निकाल दिया गया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों को हैंडल करने के लिए लगाए गए श्रमिकों की संख्या काम की मात्रा पर